VISION IAS
M N 0 8 SEP 2022 No. 3 (2)
RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2212)

Name of Candidate	राजकेश मीणा		
Medium Eng./Hindi	हिन्दी	Registration Number	60766
Center	MN	Date	08-09-22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best.

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. (150 words) 10

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद से तात्पर्य है कि संविधान के वे उपबंध जो संविधान को शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के उचित अनुपालन के साथ सरकार के तीनों अंगो से पूर्णतया पालन कराने को बाध्य करते हैं।

संविधान में संविधानवाद को रेखांकित करने वाले उपबंध :-

(1) अनुच्छेद 13 → विधायी कानूनों पर न्यायिक समीक्षा द्वारा

(2) अनुच्छेद 32 → मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक उपचार

(3) अनुच्छेद 137 → सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका के तहत पूर्णतया न्याय करने की शक्ति देता है।

(4) शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत →
(डेनवाइनेड मारली के द्वारा प्रतिपादित)
सरकार के तीनों अंगो को उचित
कार्य करने के लिए बाध्य करते है।

(5) आपातकालीन प्रावधान → विभिन्न विपरीत
परिस्थितियों को संभालते है।

(6) न्यायिक व्याख्याएँ →
इस प्रबंध की सक्रियता से
लागू करती है।

(7) नागरिक समाज की सक्रियता एवं सरकार
पर दबाव द्वारा अनुपालन

संविधानका संवैधानिक लक्ष्यों एवं
आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

CCI की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी ताकि बाजार में व्यवधानों को दूर कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।

प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका

① यह लाइसेंस राज जैसी प्रणाली का उन्मूलन करके बाजार में नियामक की भूमिका निभाकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देता है।

② सामानों की विदेशी निर्यातकों द्वारा डंपिंग, ब्लैक शैल आदि पर नियंत्रण

स्थापित करके स्वस्थ बाजार को बढ़ाती है। इससे उपभोक्ता का भी फायदा होता है और प्रतिस्पर्धी बाजार भी बनता है।

(3) ई-कॉमर्स आदि को नियंत्रित करके बाजार की कमियों को उन्मूलन कर उपभोक्ता हितैषी बाजार बनाता है।

(4) MRTP सीमा का उन्मूलन कर, FEMA के स्थान पर FERA का कार्यान्वयन करके सरकार ने उदारीकरण के दौर में CCI द्वारा नियंत्रित बाजार विकास को बढ़ावा देकर सभी हितधारकों को लाभ पहुँचाया।

कुल मिलाकर, CCI भारत में प्रतियोगी एवं स्वस्थ बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में अग्रणी संस्थान है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.
(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका है जो एकीकृत संरचना में बंधी हुई है।

भारत में 4.5 करोड़ से अधिक केस (विभिन्न स्तरों पर) लंबित हैं अतः इनके समाधान के लिए ऑनलाइन न्यायिक सेवा प्रदान के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

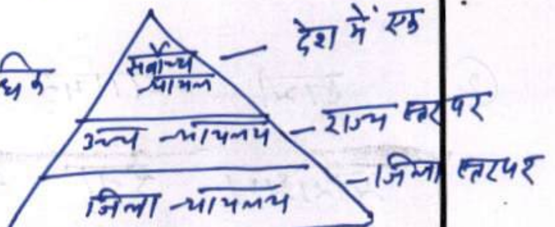

① ई-कोर्ट का क्रियान्वयन

② नेशनल डाटा ज्यूडिशियल ग्रीड
(केस की तात्कालिक स्थिति जानने के लिए)

③ विधिक अनुवाद के लिए सुवास ऐप

④ आँकड़ो के संश्लेषण में AI का अनुप्रयोग (प्रायोगिक स्तर पर)

⑤ LIBMS – Legal Information Breefing management System का क्रियान्वयन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उनके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

① न्यायपालिका के सभी स्तरों पर डिजिटल अवसंरचना का अभाव है।

② सभी न्यायिक अधिकारियों को डिजिटल प्रशिक्षण देना होगा तभी वे सहज रूप से कार्य कर सकेंगे।

③ जनता में भी इनके प्रयोग को लेकर जागरूकता सृजन करना होगा साथ ही निजता का अधिकार एवं डाटा सुरक्षा भी रखना होगा।

④ इंटरनेट प्रदान करना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का त्वरित अद्यतन आदि की चुनौती है।

न्यायिक लंबित केसों को कम करने के लिए आवश्यकता है कि ई-पहलों के कार्यान्वयन के साथ न्यायिक रिक्तियों की पूर्ति एवं बेहतर वैश्विक प्रथाओं को अपनाया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. (150 words) 10.

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ही प्रभावित है अतः दोनों में समानता एवं भिन्नता के तत्व ढूंढे जा सकते हैं।

समानता

① दोनों में विधि के शासन के सर्वोपरी स्थान दिया है।

② दोनों ~~सकारात्मक~~ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार को बढ़ावा देते हैं।

भिन्नता के तत्व

अमेरिका	भारत
① यह विधि के समक्ष सभी को बराबर या	① सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है उदा: आरक्षण

अधिकार देता है जबकि समान के साथ असमान व्यवहार के नकारात्मक प्रावधान को भी शामिल करता है।	
(2) यह हथियार रखने की अनुमति देता है	(2) भारत में हथियार रखने की अनुमति नहीं है
(3) यह अस्पृश्यता उन्मूलन, उपाधि जैसे प्रावधान को शामिल नहीं करता	(3) भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन, उपाधियों के अंत/बाल श्रम उन्मूलन, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के प्रावधान शामिल करता है
(4) यह कई आधारभूत मानवाधिकारों को भी इसमें शामिल करता है (व्यापक अधिकार शामिल)	(4) भारत में आधारभूत मानवीय मूल्य अलग से कानूनों द्वारा संरक्षित है

उपरोक्त समानता एवं भिन्नता के तत्व दोनों संविधानों में देखे जा सकते है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

स्थानीय वन निवासियों को उनके वंशानुगत अधिकारों को वन क्षेत्र में संरक्षण देकर आदिवासी समुदाय के साथ न्याय सुनिश्चित करता है ताकि वे शोषणमुक्त होकर लघु वन उपज (MFP) का संचय करके आजीविका चला सके।

कार्यान्वय धीमा एवं निष्प्रभावी रहने के कारण :-

(1) सरकार के राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते वन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को करने से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं ली जाती

(2) मुख्यधारा के लोगों का वन क्षेत्रों में प्रवेश ने उनके पारंपरिक अधिकारों

पर चोट पहुँचाई है जैसे वेदांता एवं पोस्को मामले में देखा गया

(3) जिला प्रशासन का FRA के प्रमुख पक्षों का पूर्णत कार्यान्वित न कर पाना

(4) ग्राम सभा एवं आदिवासी समुदायों में जागरूकता की कमी भी क्रियान्वयन को धीमा करती है।

(5) राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त विकास निगम द्वारा भी FRA की जद्दोजहद में अग्रणी कार्य

आगे की राह

(1) ग्राम सभा की मंजूरी को वन क्षेत्रों के अधिकतर कार्यों में अवश्य शामिल किया जाएँ

(2) जिला प्रशासन इनके मामलों पर गंभीरता से कार्य करे

(3) राजनीतिक इच्छा के साथ विधायिका एवं स्थानीय निकायों द्वारा प्रमुख प्रावधानों का कार्यपालिका द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? (150 words) 10

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए स्टॉक एक्सचेंज से धन जुटाने के लिए सृजित किया है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे तर्क :-

① समाज कल्याण सेवाओं के लिए अधिक धन की प्राप्ति सुनिश्चित होगी

② लक्ष्यों आधारित धन जुटाने से सामाजिक विकास के परिणामों में भी सुधार होगा।

③ महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता (कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह) जैसे कार्यक्रमों के लिए धन जुटाकर समाज में अपेक्षित बदलाव के कार्य किए जा सकेंगे

इस कदम का प्रभाव :-

① सरकार पर से कई सामाजिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सेवाओं का बोझ नागरिक समाज पर स्थानांतरित करना आसान होगा।

② ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों एवं गैर-सरकारी संगठनों के लिए धन जुटाना आसान होगा।

③ सामाजिक कुरीतियों के निवारण, ग्रामीण समाज के विकास द्वारा निवेश को सही दिशा देगा।

सामाजिक निवेश प्रोत्साहन में SSE की भूमिका :-

① यह बड़ी कंपनियों को CSR का धन सामाजिक प्रभाव के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

② दानार्थी संस्थान एवं लोकोपकारी संस्थानों को व्यवस्थित चैनल प्रदान कर यह निवेश को प्रोत्साहन करेगा।

कुल मिलाकर, SSE सामाजिक प्रभाव में निवेश कर प्रभावकारी योगदान दे सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.
(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मिशन की क्षमता

(1) यह टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देकर सुदूर क्षेत्रों में ~~विकास~~ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे सकता है।

(2) यह सभी नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर पूर्व के स्वास्थ्य रिकॉर्ड द्वारा स्वास्थ्य रोगियों की मदद करेगा ताकि इलाज की जड़ ढूंढी जा सके

(3) महामारी या अन्य प्रसारशील रोगों का पूर्वानुमान रखके द्वारा प्राप्त

आँकड़ों विश्लेषण करना आसान होगा

(5) विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य एजेंसियों में रोगों के निदान पर समन्वय करना आसान बनाएगा।

(6) स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता सृजित करेगा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में मदद करेगा।

मुद्दे

(1) डाटा संरक्षण के चलते डाटा सुरक्षा करना चुनौतिपूर्ण कार्य

(2) विभिन्न व्यक्तियों के हेल्थ रिकार्ड तक स्वास्थ्य कर्मियों की पहुँच निजता के अधिकार का मुद्दा भी सृजित करता है।

(3) सरकारी एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना। आँकड़ा अनुसंधान आदि भी एक चुनौतिपूर्ण कार्य

कुल मिलाकर इन मुद्दों का समाधान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सफलता सुनिश्चित करेगा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While participation of private sector in the higher education system of India is a necessity, it creates issues that need careful redressal. Discuss. **(150 words) 10**

हालांकि भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक अनिवार्यता है, लेकिन यह ऐसे मुद्दे उत्पन्न करता है जिनका सावधानीपूर्वक निवारण किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

निजी क्षेत्र की भागीदारी उच्चतर शिक्षा में नामांकन बढ़ाकर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने में बेहद महत्वपूर्ण है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित मुद्दे :-

(1) निजी क्षेत्र के पास वित्त के अभाव के चलते अनुसंधान एवं विकास (R&D) रुकता है।

(2) निजी क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की महंगी दर भागीदारी हतोत्साहित का कार्य करती है।

(3) सरकारी - निजी संस्थानों के बीच समन्वय की कमी के चलते प्रयोगशाला साझा करने में समस्या उत्पन्न।

(4) निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ अर्जित

करना है न कि सामाजिक भलाई
(5) महिला सहभागिता की निम्न दर

निवारण उपाय

(1) उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा निजी संस्थाओं में विभिन्न निकायों की शिक्षा को बढ़ाना ताकि सभी वर्गों के बच्चों को आकर्षित किया जा सके।

(2) राज्य एवं जिला स्तर पर उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए संस्थान खोले।

(3) महिला की भागीदारी बढ़ाकर

(4) वित्त की उपलब्धता बढ़ाकर एवं संस्थान फीस कम भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

उपरोक्त वर्णन के सरकारी प्रोत्साहनकारी उपाय उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ायेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Highlighting the significance of Central Asia for India, discuss the challenges in strengthening the Indo-Central Asian relationship. (150 words) 10

भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत-मध्य एशियाई संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

मध्य एशिया से ~~सामित~~ भारत के ऐतिहासिक काल से ही मजबूत संबंध रहे हैं। वर्तमान में भी शंघाई सहयोग संगठन आदि मंचों द्वारा भी संबंधों में सततता बनी हुई है। मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तुर्केमिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि शामिल है।

भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व :-

1. आर्थिक रूप से वृहद बाजार है जो भारत को निर्यात करने के अवसर प्रदान करता है।
2. पाक - अफगान में आतंकवाद को कम करने में सहयोग में योगदान
3. यूरेनियम, गैस आदि जैसे वृहद संसाधनों की ये देश आपूर्ति कर सकते हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा।
4. भारत की 'कनेक्ट मध्य एशिया नीति' की सफलता सुनिश्चित करने तथा भारत की छवि को वैश्विक पटल पर बढ़ाने-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एवं UNSC की सदस्यता में सहयोग के लिए मध्य एशिया महत्वपूर्ण

(5) ताजाकिस्तान में भारत का सैन्य अड्डा भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

चुनौतियाँ

(1) चीनी कारक क्योंकि सभी देश चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव के भाग है।

(2) सीमित बाजार. भागीदारी एवं व्यापारिक संबंध क्योंकि पाकिस्तान के चलते सीधे स्थल-मार्ग द्वारा पहुँच नहीं है चाबहार बंदरगाह होते हुए सामान - आदान प्रदान होता है।

(3) इन देशों में कट्टरवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का तेजी से फैलाव

(4) लैंडलॉक्ड होने के चलते व्यापार शिथिल

कुल मिलाकर, चुनौतियों के बावजूद मध्य एशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण भागीदार देश है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role that the Indian diaspora can play in the making of "Aatmanirbhar Bharat" (self-reliant India). Also, mention the challenges in this regard. **(150 words) 10**

"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारतीय डायस्पोरा विश्व में सर्वाधिक मात्रा में फैले हुई है इनका निवेश विश्व के प्रत्येक देश में पाया जाता है। ये डायस्पोरा भारत में वृहद मात्रा में रेमिटेंस भेजकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आत्मनिर्भरता में
डायस्पोरा की भूमिका

(1) भारत के साथ विभिन्न देशों में ये शांति राजदूत के रूप में कार्य कर राजनीतिक संबंधों को मजबूती देते हैं।

(2) ~~बाजार निर्माण को देखकर~~ भारतीय निर्यातकों के महत्वपूर्ण बाजार के रूप में कार्य होते हैं।

(3) भारत की सॉफ्ट पॉवर खेल, योग, फिल्म, भोजन आदि को बढ़ाते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) विभिन्न वैज्ञानिक एवं इंजीनियर भारत के लिए कर तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे सकते हैं।

(3) कृषि, जैव, उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर GDP वृद्धि में योगदान देते हैं। एवं देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं।

(6) स्थानीय उद्योगों में निवेश कर धन की आवश्यकता पूरी करते हैं।

चुनौतियाँ :-

(1) भारत के लिए काम करने के लिए उन्हें अच्छी सुविधाएँ प्रदान करना एवं उन्हें देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करना

(2) पर्याप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान माहौल प्रदान करना

इस प्रकार प्रवासी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी ~~क्षेत्र के~~ स्वायत्त संस्थानों के विकास को बढ़ावा देना है ताकि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण बढ़ावा द्वारा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

74वें संशोधन की कमियाँ

1. नियमित चुनावों का अभाव इसके विकास की गति को धीमा करता है
2. प्रतिनिधियों में जागरूकता एवं अधिकारों को लेकर समझ का अभाव स्थानीय शहरी निकायों के विकास को शिथिल करता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ वित्त का अभाव

स्थानीय शहरी निकाय स्वं के राजस्व स्रोतों से केवल एक तिहाई राजस्व ही जुटा पाते है। (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21) बाकि हिस्से के लिए केन्द्र - राज्य अनुदान एवं बाजार ऋण पर निर्भर है।

④ शक्तियों का राज्य विधानमंडल द्वारा पर्याप्त आवंटन नहीं होने के चलते आवंटित 18 विषयों के सामाजिक - आर्थिक विकास को भी पूर्णता में नहीं कर पाते।

⑤ योजना निर्माण में सीमित भागीदारी क्योंकि जिला योजना समिति एवं महानगर योजना समिति की नीतियां पर कोई अधिकार नहीं होती है।

⑥ निकायों में राजनीतिक हस्तक्षेप आदि है काम को करने में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुदृढ़ करने के उपाय

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित

(i) वित्त का हस्तांतरण अधिक किया जाए
(ii) राजनीतिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण
प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण किया जाए
(iii) शक्तियों को और अधिक जमीनी स्तर की संस्थाओं को आवंटित किया जाए (केरल मॉडल अपनाया जाए)

१५वीं आयोग द्वारा अनुशंसित

(iv) केन्द्रीय राजस्व पूल से एक निश्चित हिस्सा वित्त आयोगों द्वारा आवंटित किया जाए
(v) करों को संग्रहित करने के अधिक अधिकार जमीनी स्तर पर सौंपे (जैसे संपत्ति कर मनोरंजन कर आदि)

इन सबके अलावा योजना निर्माण का कार्य जमीनी स्तर से ही शुरू किया जाए साथ ही स्थानीय शहरी निकायों में मानव संसाधन क्षमता आदि को भी बढ़ाया जाए ताकि होलिस्टिक विकास संपन्न हो सके

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

नौवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल की गई ताकि भूमि सुधार जैसे प्रगतिशील कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। हालांकि न्यायपालिका ने (विभिन्न निर्णयों के) केशवानंद भारती वाद 1973 के बाद शामिल प्रत्येक कानून की न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा है।

9वीं अनुसूची से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी एवं संसदीय आधिपत्य का सृजन [illegible]

(1) 9वीं अनुसूची द्वारा विधायिका द्वारा कुछ राज्य एवं केन्द्रीय कानूनों की संवैधानिक समीक्षा को रोका गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिससे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर चोट पहुँची है।

(2) इस अनुसूची द्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता की बजाय संसदीय सर्वोच्चता को बढ़ाया है जो कि कथन के पक्ष में ही इंगित प्रतीत होता है

(3) सरकार का मानना है कि संसाधनों के समान वितरण के लिए एवं नीति-निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए उपरोक्त कदम उठाए गए हैं

(4) फिर भी इस अनुसूची द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति विभाजन असंतुलित होता है क्योंकि यह न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करता है। जो कि न्यायिक समीक्षा संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायपालिका का महत्वपूर्ण अधिकार है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) ~~प्रत्येक ऐतिहासिक~~

न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों में 1973 के बाद अनुसूची में शामिल प्रत्येक कानून की न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित कर दिए है संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित किया है।

कुल मिलाकर, सरकार समावेशी विकास के लिए 9वीं अनुसूची को शामिल करना चाहती है वहीं न्यायपालिका संवैधानिक सर्वोच्चता को। आगे समाधान के लिए दोनों के बीच एक महीन संतुलन की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक आदर्शों की सफलता सुनिश्चित हो सके।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

भारत में संघीय शासन ~~प्रणाली~~ प्रणाली को अपनाया है जिसमें केन्द्र और राज्य शक्तियों को साझा करते हैं। संघवाद में ~~केन्द्र~~ ~~एवं~~ राज्यों के बीच भिन्नता को असममित संघवाद कहते हैं।

असममिति द्वारा मांगों के समायोजन के उदाहरण.

① जम्मू एवं कश्मीर को अनुच्छेद 370 (अबरद्द) द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया ताकि तत्कालीन J&K की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके

② संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों के विकास के लिए ~~राज्यों~~ राज्यपाल को विशेष

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शक्तियों का आवंटन द्वारा लोकतांत्रिक मांगों का समायोजन किया है।

(7) विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाना
(वर्तमान में 11 राज्यों को यह दर्जा है।)
(8 उत्तर पूर्वी + हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर)

(5) पाँचवी एवं छठी अनुसूची द्वारा कई संवैधानिक प्रावधानों पर सीमाएँ

उपरोक्त उदाहरण अल्पसंख्यकों के उदाहरण है

अल्पसंख्यकों के पक्ष में तर्क

(1) इससे लोगों की मांग समायोजित कर लोकतंत्र को मजबूती मिलती है
(2) क्षेत्रवाद, अलगाववादी भावनाएँ शांत
(3) अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल संभव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) आदिवासी अधिकार सुरक्षित
(5) प्राकृतिक पिछड़ेपन का समाधान

असममिति के विपक्ष में तर्क

(1) इससे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
(2) संविधान की संघीय व्यवस्था कमजोर होती है।
(3) यह 'देश के भीतर देश' व 'राज्य के भीतर राज्य' की स्थिति को दर्शाता है।
(4) यह समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं है।
(5) यह राज्यों के समावेशी विकास में बाधाकारी

कुल मिलाकर, फिर भी असममिति विभिन्न लोगों को समायोजन दे सकती है लेकिन आवश्यकता भी है कि इसे एक निश्चित समय सीमा तक ही रखकर सुधार किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250 words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

राज्य वित्त आयोग की स्थापना 72वें एवं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों (243K) ~~के क्रियान्वित करवाने के लिए~~ के तहत की गई है ताकि राज्य और स्थानीय स्तर पर वित्तीय तंत्र के वितरण पर सुझाव दे सके। वहीं केन्द्रीय वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित है।

राज्य वित्त आयोग का राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में योगदान :-

(1) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त आयोग के निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य की वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) राज्य और पंचायतों की स्थिति का राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग द्वारा ही केन्द्र स्तर पर उपलब्ध करवाया जाता है।

(8)

राज्य वित्त आयोग की ~~~~ राजकोषीय संघवाद के बढ़ावा देने के प्रयास में तर्क !-

(1) राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है अतः राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने में इसका नगण्य प्रभाव है।

(2) दोनों के बीच संवाद का अभाव है।

(3) दोनों के उद्देश्य भी अलग -अलग है।

(4) राज्य वित्त आयोग नियमित नहीं है साथ ही कहीं राज्यों में स्थापित भी नहीं किए गए है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

कुल मिलाकर, अधिक प्रभावी न होने पर भी ~~राज्य~~ राज्य वित्त आयोग केन्द्र वित्त आयोग को सहयोग देकर एक नीचा तक राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है। और मजबूत राजकोषीय संघवाद के लिए GST परिषद की तरह वित्त आयोग परिषद का गठन कर राजकोषीय संघवाद को बढ़ाया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.

(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

नौकरशाही देश के शासन की रीढ़ की हड्डी है। कुछ विचारक 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' पर बल देते हैं ताकि प्रशासन के बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। और शासन की सफलता को बढ़ाया जा सके।

नौकरशाही के आकार को कम करने के पक्ष में तर्क

(1) इससे प्रशासन में उच्चस्तर पदानुक्रम होगा और बेहतर जवाबदेही का क्रम सुनिश्चित हो सकता है ताकि कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाया जा सके।

(2) सरकारी खर्चों में कमी होगा

जिससे कुछ कार्यों को विशेषज्ञों को आउटसोर्स कर बेहतर ढंग से कराया जा सकता है।

(3) प्रशासन में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के चलते अब नौकरशाही की आवश्यकता भी घटती जा रही है।

(4) इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, भाई-भतीजावाद कम होकर सिविल सेवा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

(5) मंत्रालयों एवं विभागों की संलग्नता कर स्टाफ को कम करने से भी कार्यों में कुशलता ~~●~~ एवं प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

विपक्ष में तर्क

(i) पहले से ही प्रशासन में स्टाफ की कमी है साथ ही डॉक्टर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निरंतर बढ़ता जा रहा है अतः यह विचार अभ्युक्ति है जैसे - UNODC 1 लाख जनसंख्या पर 288 पुलिस का प्रस्ताव है वही भारत में केवल 180 ही है।

② आकार घटने से कुशलता घट सकती है योजनाओं का क्रियान्वयन कम होगा, कुशासन बढ़ेगा जिससे जनता की जटिलता बढ़ सकती है

फिर भी रोजगार संतुलन के आधार पर अनुसंधान कर ऐसे कदम उठाए जा सकते है पर ध्यान रहे कि जनता को कमी के चलते न तो शासन का अभाव हो न ही अधिकता के शासन का दवाब सृजित हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

मंदिरों को विभिन्न राज्य विधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। कई बार प्रशासन पर अनियमितताओं के चलते मंदिरों में राज्य के हस्तक्षेप पर सवाल खड़े होते हैं।

मंदिर प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप के कारण

(1) वित्त (दान) का वृहत स्रोत होते हैं अतः राज्य यानी केन्द्र में उनका संरक्षक है।

(2) सामाजिक आर्थिक विकास के वाहक होते हैं क्योंकि दक्षिणा में मंदिर शिक्षा आदि वितरण का भी कार्य करते हैं।

(3) जनता की बढ़ती श्रद्धा के कारण कानून-व्यवस्था के संरक्षण के लिए हस्तक्षेप जरूरी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पुलिस प्रबंधन में राज्य हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दे

(1) ट्रेनिंग कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप

(2) स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के साथ बदसलूकी आदि का आरोप भी लगता है।

(3) राज्य का कई बार अनावश्यक हस्तक्षेप पुलिस विकास समिति के सामने चुनौती खड़ी कर देता है।

आगे की राह

(1) राज्य विधान द्वारा स्पष्ट कानून बनाकर नैतिक मानक जवाबदेही और प्रबंधन के उपाय सुनिश्चित किए जाएँ

(2) केंद्र द्वारा भी राज्यों की सहायता के लिए एक आदर्श कानून बनाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) मंडि में प्रशासनिक अनियमितताओं पर त्वरित कार्यवाही हो।

(5) मंडि प्रशासन में नागरिकों आदि अन्य हितधारकों की भागीदारी से प्रबंधन किया जाए।

उपरोक्त उपाय मंडियों के उचित प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायक होंगे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What do you understand by feminisation of old age? Highlight the issues associated with it in the Indian context. Also, mention the measures taken by the government in this regard. (250 words) 15

वृद्धावस्था के नारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

वृद्ध पुरुष एवं स्त्रियों में से नारियों के अनुपात बढ़ने को वृद्धावस्था का नारीकरण कहते है। बढ़ती महिला जीवन प्रत्याशा के चलते ~~हैं~~ वृद्धों में महिला का अनुपात बढ़ रहा है।

भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दे

1. पुरुष सहयोगी के जल्दी मरने से भावनात्मक शून्यता का बढ़ना। जिससे मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न होता है।

2. स्वास्थ्य संबंधी बिमारियों ~~को बढ़ाना~~ का समय पर इलाज नहीं होने से वृद्धों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ रहा है।

3. परिवार के अन्य लड़कों के प्रवास

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के चलते उनकी सुरक्षा की चिंताएँ भी बढ़ती जा रही है।

(4) रोजगार के साधनों के अभाव या आय का अभाव इन्हें महिलाओं के जीवन का दुभार बना रहा है।

(5) महिलाओं पर बढ़ते अपराध एवं शोषण के प्रति भी वे अधिक निर्भरशील है।

(6) सहायक सुरक्षा उपकरणों का अभाव जीवन में नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

सरकार द्वारा उठाएँ गए कदम

(1) माता पिता भरण पोषण भत्ता अधिनियम 2007: बच्चों पर माता-पिता के भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी तय करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

के तहत बुजुर्गों को सहायक उपकरणों की आपूर्ति की जाती है।

(3) वृद्धावस्था पेंशन योजना

के तहत मौद्रिक मदद

(4) वृद्धावस्था आश्रमों की स्थापना

ताकि वह अपने मित्रों के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

(5) जन वितरण प्रणाली (NFSA-2013) के तहत खाद्यान्न आपूर्ति

आगे की राह

वृद्धावस्था के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार कर विभिन्न रोगों का निवारण करना चाहिए साथ ही सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए जाएं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Given its impact on both individual resilience and the resilience of the economy, is there a case for strong universal social protection in India? Discuss. **(250 words) 15**

व्यक्तिगत लचीलेपन और अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता दोनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, क्या भारत में सुदृढ़ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है? विवेचना कीजिए।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य सरकार द्वारा नागरिकों को एक निश्चित समयावधि में कुछ मौद्रिक राशि देना ताकि वे अपना जीवन-बसर आसानी से चला सके। बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान में यह सामाजिक सुरक्षा प्रभावी है। कोविड-19 के दौरान कुछ समय के लिए ऐसे अल्पकालिक प्रयोग किए है।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

1. बेरोजगारी की दर 6% के आसपास है जो इसकी आवश्यकता को बताती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी के समाधान के लिए

(3) कोविड-19 एवं यूक्रेन-रूस युद्ध जनित मंदी ने रोजगारी स्थिति को बढ़ावा दिया है।

(4) गरीबी (22%) को समाप्त करने के लिए

(5) लोगों की बुनियादी आकांक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यकता

(6) रोजगार प्राप्ति को लेकर विरोध को शांत करने के उपयोगी

(7) औद्योगिक मंदी के चलते उत्पन्न बेरोजगारी का शमन

विपक्ष के तर्क

(1) आर्थिक स्थिति को देखते हुए अव्यवहार्य

क्योंकि पहले ही व्यय निर्धारित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सीमा (3%) ~~की सीमा~~ के अतिरिक्त राजकोषीय घाटा (6%) बना हुआ है।

(2) स्थायी समाधान नहीं, यह लोगों को अकर्मण्य बना सकता है।

(3) विभिन्न योजनाओं (PDS मनरेगा) आदि के रूप में पहले से ही प्रचलन में।

(4) रिसाव की समस्या होगी भारत में 90% अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है अतः लाभार्थी का निर्धारण जटिल

(5) पूंजीगत निवेश को प्रभावित करेगा

फिर भी कुछ विशेष पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कदम दीर्घकालिक समावेशी विकास में सहायक साबित हो सकते है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There have been arguments that with the old global multilateral order failing to manage rising challenges, issue-based coalitions are gaining traction and have become the arenas of functional cooperation. Discuss.
(250 words) 15

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे-आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

शीतयुद्ध के समय स्थापित बहुपक्षीय व्यवस्था अब मुद्दे आधारित गठबंधनों यथा आसियान, क्वाड, ऑकस आदि से प्रवर्तित होती जा रही है।

पुरानी वैश्विक व्यवस्था की विफलता के कारण

(1) एशिया का तीव्र गति से उभार एवं चीन व भारत का नवीन शक्ति के रूप में उभरना, पश्चिम के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आना

(2) वैश्विक मुद्दों या सहमति का अभाव जैसे कृषि सब्सिडी पर WTO में, UNSC सुधार में आदि के चलते

(3) बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों एवं अपने आन्तरिक हितों अनुकूल संबंधों के चलते।

(4) WB, IMF के समानांतर ADB, AIIB जैसे बैंकों का उदय विकासशील देशों की स्थानीय जरूरतों का पूरा करने की क्षमता रखता है।

(5) वैश्विक संस्थाओं का अलोकतांत्रिक दृष्टिकोण एवं पश्चिम के पक्ष में पक्षपात

कुछ आधारित गठबंधन की लोकप्रियताओं

(1) रूस यूक्रेन महामारी की तुलना के लिए क्वाड, आकस आदि का गठन

(2) रणनीतिक स्वायत्तता बनाये रखने एवं क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों को बढ़ावा देने में सहायक
जैसे Brics, ASEAN, RCEP, SCO आदि

(3) व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न FTA आदि

(4) आपदा प्रबंधन, आदि में सहयोग

(5) अपने हितों को बढ़ावा देने के कारण देश इन्हें आधारित गठबंधन को बढ़ावा देते हैं जैसे G-4 UNSC रिफॉर्म हेतु

फिर भी बहुपक्षीय गठबंधन निष्पक्ष वैश्विक सहमति के निर्माण के लिये भारत की आकांक्षाओं को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India intends to achieve a balanced and optimal development of energy infrastructure in the South-Asian region through mutual understanding and cooperation. In light of this statement, discuss the need as well as existing gaps in South Asia's energy cooperation. **(250 words) 15**

भारत पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में एक संतुलन और उसका इष्टतम विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता और इस संदर्भ में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए।

दक्षिण एशिया सात देशों से मिलकर बना है जिसके भारत इसके केंद्र में है।

दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता

(1) ऊर्जा के स्वतंत्र स्रोतों का अभाव —
अधिकतर देश आयात पर निर्भर अतः राजस्व की बचत के लिए सहयोग जरूरी

(2) एक-दूसरे की निकटता के चलते स्रोत की साझा हो।
जैसे पन बिजली के लिए भारत को नेपाल एवं भूटान का सहयोग जरूरी है।

(3) विशाल जनसंख्या की आपूर्ति के लिए

(4) आधिकतर हिमालय की रेखा क्षेत्र के अतः और ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता

(5) जहाँ विकासशील देश हैं अतः परमाणु प्रौद्योगिकी ऊर्जा के उत्पादन के लिए सहयोग जरूरी

(6) कोयला की निरंतर आपूर्ति के लिए आपस के देशों के सहयोग की आवश्यकता है

विधमान कमियाँ

(1) प्रौद्योगिकी का अभाव (परमाणु ऊर्जा के लिए)

(2) निवेश की कमी

(3) ठोस संस्थागत व्यवस्था का ना होना

(4) कोयला खनन आदि की उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव

(5) पाकिस्तान का भारत विरोधी रुख

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

फिर भी ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के
लिए [illegible] मंत्रालय में (सहयोग) बढ़ाना होगा